Volume 1; Issue 3
July to September 2025

E-ISSN: 3049-1134

International Journal of Political Studies

Peer Review **Indexed** **Refereed Journal**

Quarterly International Research Journal

International Journal of Political Studies
E-ISSN: 3049-1134
https://www.polsci.in
https://doi.org/10.5281/zenodo.16554814
Volume 1; Issue 3; July to September 2025; Page No. 25-39
Peer Review, Indexed and Refereed Journal
Date of Publication: 28-07-2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: विकसित भारत की आधारशिला

सरताज सिंह
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान
पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़
ईमेल: singhsartaj485@gmail.com

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी कदम है जो भविष्य में भारत को एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा की और लेकर जायेगा। यह नीति न केवल शिक्षा को आधुनिक समय की आवश्यकताओं से जोड़ती है बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी जोर देती है। विशेष रूप से इस नीति में प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग पर बल दिया गया है जिससे बच्चों की नींव मजबूत होगी और वे अपनी संस्कृति से जुड़ते हुए सरलता से नई चीजो को सीख पाएगे। इसके साथ ही इस नीति में कौशल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है जिससे छात्रों को व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त होगी। डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस नीति में डिजिटल उपकरणों और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को भी समाहित किया गया है जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकी युग में सक्षम बनाने का अवसर मिलेगा। शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ यह नीति भारत को एक वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति समावेशी और लचीले शिक्षा ढांचे के माध्यम से हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर प्रदान करती है जिससे सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह नीति छात्रों में कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा, कौशल, नवाचार और डिजिटल युग के माध्यम से भारत को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने का अवसर प्रदान करती है और यह नीति देश के युवाओं को

आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना से सशक्त कर एक विकसित भारत की नींव रखती है। इस शोध पत्र में विकसित भारत की आधारशिला इस नई शिक्षा नीति से कैसे रखी जा सकती है और कैसे इसके विभिन्न आयाम भारत को आने वाले समय में मजबूती प्रदान करंगे इस विषय पर गहन अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द: विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत ,डिजिटल शिक्षा, कौशल शिक्षा, समग्र विकास, मातृभाषा में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक अभूतपूर्व बदलाव की शुरुवात है। यह नीति भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र और वैश्विक शक्ति बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। लगभग 34 वर्षों के बाद, इस नई नीति ने शिक्षा को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया है। इस शिक्षा नीति का यह नया ढांचा छात्रों के संपूर्ण विकास, कौशल निर्माण और नवाचार पर केंद्रित है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, बल्कि इसे रोजगार के साथ जोड़कर सुलभ और समावेशी बनाना भी है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जहां जनसंख्या का लगभग 50% से 60% हिस्सा 30 वर्ष से कम आयु का है। विशेषज्ञो के मुताबिक 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा कार्यबल वाला देश बन जाएगा। ऐसे में शिक्षा प्रणाली का सशक्त और आधुनिक होना अत्यंत आवश्यक है। आल इण्डिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात केवल 27.1% है और नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य इसे 2035 तक 50% करना है। इसके लिए इस नीति में डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान पर विशेष जोर दिया है। (AISHE Report, 2021-22) [1] नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 के ढांचे में विभाजित किया है, जो आयु और छात्रों की मानसिक क्षमताओं के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसमें प्रारंभिक बाल शिक्षा में मातृभाषा में पढ़ाई के प्रावधान से छात्रों की बौद्धिक क्षमताए मजबूत होगी वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होगे। इस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल शिक्षा पर बल देना भी है।

यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत में डिजिटल शिक्षा के व्यापक रूप अपनाने से लगभग 9 करोड़ छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकेगी साथ ही कौशल विकास और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों को शामिल करके यह नीति छात्रों को उद्यमिता और आधुनिक तकनीकी दुनिया

के लिए तैयार करने का कार्य करेगी। (UNESCO Report. 2021) [13] महात्मा गांधी ने भी कहा था, शिक्षा का उद्देश्य केवल रोज़गार पाना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण होना चाहिए। यह विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समग्र दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है। यह नीति बिना किसी भेदभाव के शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाती है ताकि समाज के हर वर्ग का छात्र शिक्षा ग्रहण करके भारत को विकसित बनाने में अपना सहयोग दे सके। यह शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शक्ति और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए एक ठोस आधारशिला है और यह शिक्षा के माध्यम से देश को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाएगी। यह नीति भविष्य की पीढ़ियों को आत्मनिर्भर, नवाचारी और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में पूर्ण रूप से अग्रसर है।

शोध पत्र के उदेश्य

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत की शिक्षा प्रणाली में नए दृष्टिकोण और सुधारों की दिशा को समझना।

2. कौशल शिक्षा और रोजगार सृजन के लिए इस नीति द्वारा प्रस्तुत नए रास्तों को पहचानना और उनका प्रभाव जानना।

3. शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर भारत को एक सशक्त वैश्विक शक्ति और ज्ञान आधारित राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया का अन्वेषण करना।

4. मातृभाषा में शिक्षा के माध्यम से छात्रों की बौद्धिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाने के फायदों पर विचार करना।

5. समावेशी और समानता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति द्वारा उठाए गए कदमों से समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा की पहुंच का अवलोकन करना।

6. अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की भूमिका और इसके संभावित प्रभावों को समझना।

साहित्य समीक्षा

Bal, D., & Singh, K. (2023). National Education Policy-2020: A driving force for higher education of India. International Journal of Research in Library Science, 9(4): इस शोध पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 के उच्च शिक्षा पर प्रभाव का गहन विश्लेषण किया गया है। शोध पत्र में यह बताया गया है कि इस नीति के तहत शिक्षा प्रणाली में किए गए सुधार जैसे अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता सुधार भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम हैं। इस शोध में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस नीति ने समावेशिता और प्रवेश की समानता को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों के छात्रों को समान अवसर मिल सकें। समाज की विभिन्न श्रेणियों से आने वाले छात्रों के लिए यह नीति

विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, यह शोध उच्च शिक्षा में नई संभावनाओं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करने का प्रयास करता है। इस अध्ययन में यह भी बताया कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

Verma, H., & Kumar, A. (2021). New Education Policy 2020 of India: A theoretical analysis. International Journal of Business and Management Research 9(3): इस शोध पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 की आलोचनात्मक समीक्षा की गई है, जिसमें नीति के सकारात्मक पहलुओं के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर भी विचार किया गया है। शोध पत्र के लेखक ने बताया है कि मातृभाषा में शिक्षा और डिजिटल शिक्षा जैसे सुधारों से भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और समान अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है परंतु इस नीति के लागू होने के बाद सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इसके प्रभावी कार्यान्वयन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस शोध में यह भी प्रशन उठाया गया है कि क्या भारत में इस नीति के उद्देश्यों को सही तरीके से लागू किया जा सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आर्थिक विषमताएं हैं। इसके बावजूद, यह शोध नई शिक्षा नीति के दीर्घकालिक लाभों और भविष्य में इसके विकास पर भी ध्यान केंद्रित करता है और इसमें इस नीति के भविष्य के परिणामों और संभावनाओं को विस्तार से समझाया है।

Kumar, A. (2021). New education policy (NEP) 2020: A roadmap for India 2.0. in W. B. James, C. Cobanoglu, & M. Cavusoglu (Eds.), Advances in global education and research, Vol. 4: इस शोध पत्र में लेखक के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत भारत के शिक्षा तंत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दृष्टि प्रस्तुत की गई है। लेखक ने इस शोध पत्र में विस्तार से बताया है कि कैसे इस नीति के माध्यम से प्रौद्योगिकी और नवाचार को शिक्षा तंत्र में शामिल किया जा रहा है ताकि भारत के छात्रों को उच्च मानकों की शिक्षा मिल सके। यह शोध पत्र विशेष रूप से उच्च शिक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में नई शिक्षा नीति के योगदान का विश्लेषण करती है और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि प्रौद्योगिकी के साथ शिक्षा को जोड़ने से छात्रों को नवीनतम शिक्षा और नवाचार के लिए तैयार किया जा सकता है। इस शोध पत्र में लेखक ने यह भी सुझाया है कि ज्ञान आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए भारत को प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में और अधिक सुधार करने होंगे तभी हम आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और देश का विकास हो पायेगा।

Sharma, N. (2024). India's National Education Policy (NEP) 2020: Reimagining and revolutionizing higher education: A review. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science, 6(7): इस शोध पत्र में लेखक ने यह बताया है कि कैसे शिक्षा के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता, समाज कल्याण, और हरित विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस शोध पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 ने समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं, जैसे महिला शिक्षा, दिव्यांग छात्रों के लिए सहायक उपाय और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए विशेष शिक्षा योजनाएं बनाई गई है। इस शोध पत्र में यह बताया गया है कि कैसे यह नीति समावेशिता और आधुनिक तकनीक के माध्यम से भारत में शिक्षा प्रणाली को सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बदलने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा इसमें लेखक ने यह भी सुझाव दिया है कि यह नीति सतत शिक्षा और हरित विकास के माध्यम से भारतीय समाज को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाएगी।

Betsurmath, C. G., & Chidambaram, S. B. (2024). National Education Policy 2020, India: A planned change management requisite for higher education institutions. Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8(9): इस शोध पत्र में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस किया गया है। इस अध्ययन में बताया गया है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है और इस नीति के अंतर्गत नए पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को उनके कौशल में वृद्धि करने का अवसर दिया जा रहा है। यह शोध पत्र यह भी दर्शाता है कि कैसे प्रौद्योगिकी और नवाचार को शिक्षा में शामिल करके युवाओं को आर्थिक और सामाजिक विकास में भागीदार बनाया जा सकता है। साथ ही, यह अध्ययन कौशल आधारित शिक्षा के लाभों को भी रेखांकित करता है और इसे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानता है। इसके अलावा यह शोध पत्र यह भी दर्शाता है कि व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देकर भारत के रोजगार संकट को हल किया जा सकता है।

शोध में अंतर (रिसर्च गैप)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर किए गए पिछले अध्ययनो और शोध कार्यों के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहनता और समग्रता की कमी स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष आई है। इस नीति के बारे में अधिकांश शोध शिक्षा नीति के संरचनात्मक और अवधारणात्मक पहलुओं पर केंद्रित हैं लेकिन जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों,

जैसे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा के प्रभाव, स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम सामग्री की उपलब्धता और कौशल आधारित शिक्षा के परिणामों पर समर्पित अध्ययन की कमी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की भूमिका को गहराई से समझने के लिए विश्लेषणात्मक शोध अपर्याप्त हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पुनर्स्थापित करने के प्रयासों के प्रभाव का आकलन करने और उन्हें वैश्विक मंच पर कैसे प्रस्तुत किया जाए इस पर भी सीमित अध्ययन उपलब्ध हैं। यह आवश्यक है कि इस नीति के बहुआयामी प्रभाव को समझने के लिए अंतःविषय दृष्टिकोण अपनाया जाए और आधुनिक तकनीक और पारंपरिक मूल्यों के सामंजस्य पर अधिक शोध किया जाए। इस शोध पत्र में मेरा यह प्रयास है कि जो पहलु अनछुए रह गए है जिन पर विस्तृत अधयन्न उपलब्ध नही है उनके बारे में मैंने इस शोध पत्र में गहन अधयन्न करके चर्चा करने का प्रयास किया है।

शोध प्रश्न

1. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को आत्मनिर्भर और विश्वशक्ति बनाने की दिशा में एक ठोस आधारशिला प्रदान करती है?

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समग्र दृष्टिकोण भारतीय शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार समावेशी, गुणवत्ता-आधारित और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा?

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान देने से भारतीय युवाओं के रोजगार अवसरों में क्या परिवर्तन आएगा और यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किस प्रकार सहायक होगा?

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा डिजिटल शिक्षा और प्रौद्योगिकी के एकीकरण से भारतीय शिक्षा तंत्र की समग्र गुणवत्ता और पहुंच में किस हद तक सुधार हो सकता है?

5. क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक मानकों के अनुरूप सुधारने के लिए आवश्यक संरचनात्मक बदलावों को सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम है?

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के सिद्धांत से भारत में शिक्षा के सामाजिक समावेश और सांस्कृतिक समृद्धि में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे?

शोध प्रविधि

इस शोधपत्र में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध विधियों का समावेश किया गया है ताकि नई शिक्षा नीति के प्रभावों का गहराई से विश्लेषण किया जा

सके। सबसे पहले द्वितीयक स्रोत के माध्यम से सरकारी रिपोर्ट्स, शोध पत्र, नीति दस्तावेज़ और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण का अध्ययन किया गया है जिससे इस नीति के उद्देश्यों और योजनाओं को समझने का अवसर मिला। इसके बाद ऑनलाइन साक्षात्कारो को देखा गया जिसमें शिक्षाविदों, शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों और विद्यार्थियों से संबंधित सवाल पूछे गए हैं ताकि उनके अनुभव और दृष्टिकोण को सामने लाया जा सके। ये ऑनलाइन साक्षात्कार जो राष्ट्रीय टी.वी चैनल के द्वारा किए गए है ये मुख्य रूप से डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास, मातृभाषा में शिक्षा जैसे पहलुओं पर केंद्रित थे। प्राप्त आंकड़ों को सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से रूपांतरित किया गया ताकि नीति के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और चुनौतियों का मूल्यांकन किया जा सके। इसके अतिरिक्त द्वितीय स्रोत के रूप में पुरानी केस स्टडी जो हो चुकी है उन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है जहां इस नीति के प्रभाव पहले से ही देखे जा रहे हैं ताकि उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। इस शोध का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के कार्यात्मक प्रभाव और इसके दीर्घकालिक परिणामों को समझना है ताकि इस नीति के माध्यम से भारत की शिक्षा प्रणाली को और बेहतर और समावेशी बनाया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विकसित भारत का संकल्प

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में प्रस्तुत की गई है। यह नीति विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करके भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख स्थान दिलाना है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक समावेशिता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस नीति के अनुसार, कौशल शिक्षा के लिए 2025 तक 50% युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी और वे कृषि, निर्माण और नवाचार के क्षेत्रों में सकारात्मक योगदान दे सकेंगे। इसके अतिरिक्त, मातृभाषा में शिक्षा का समर्थन करते हुए इस नीति में पहली से पांचवीं कक्षा तक मातृभाषा को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण और प्रसार को बढ़ावा देना है। (गुप्ता, म. 2022) {6] इसके अलावा इस नीति में डिजिटल शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत सरकार के अनुसार राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मिशन के तहत 2025 तक भारत में 80% विद्यार्थियों

को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य है। यह कदम देश के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए आवश्यक है क्योंकि डिजिटल शिक्षा न केवल छात्रों के ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि यह भारत के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक समावेशिता और गुणवत्तापूर्ण सुधार को भी प्रोत्साहित करती है। भारत के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में वर्तमान में 44वें स्थान पर होने के बावजूद इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से इसे अगले 5 वर्षों में 20 स्थान ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप प्रदान कर रही है और आज जरूरत इस बात की है कि हम इस शिक्षा नीति को सफल बनाने में अपना पूर्ण रूप से सहयोग दे।

मातृभाषा में शिक्षा से विकसित भारत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा को शिक्षा का प्रमुख माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा से छात्रों के सीखने की क्षमता और समझ में काफी सुधार होता है। भारत में विभिन्न भाषाओं का एक बड़ा सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर है और इस नीति में इस विविधता को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा के उपयोग को प्राथमिक शिक्षा के लिए जरूरी किया जा रहा है ताकि हर छात्र अपनी मूलभाषा में सहजता से शिक्षा प्राप्त कर सके ताकि उसे बेहतर ढंग से सीखने और समझने में कोई समस्या न हो। एन.सी.आर.टी एक रिपोर्ट के अनुसार, 80% छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा से बेहतर समझ और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। (NCERT Report, 2021-22) [8] इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षा से बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है क्योंकि वे जिस भाषा में सहज होते हैं उसी में अपनी बातों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों के लिए फायदेमंद है जहां स्थानीय भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इस नीति के अनुसार 2025 तक भारत में सभी प्राथमिक स्कूलों में मातृभाषा में शिक्षा देने का लक्ष्य है, जिससे बच्चों की शैक्षिक यात्रा की शुरुवात उनकी मातृभाषा से हो और वे मानसिक रूप से बेहतर ढंग से विकसित हो सकें। मातृभाषा में शिक्षा का यह प्रयास भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा और छात्रों की सामाजिक समावेशिता को सुनिश्चित करेगा।

कौशल शिक्षा के माध्यम से विकसित भारत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल शिक्षा को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई है क्योंकि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम है। इस नीति का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को ऐसे

प्रशिक्षण और दक्षताएँ प्रदान करना है जो उन्हें रोजगार योग्य बना सकें और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इस नीति के तहत कौशल शिक्षा को 10वीं और 12वीं कक्षा के स्तर पर भी पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकें। इस नीति के अनुसार 2025 तक 50% युवा छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है जिस कारण से यह कदम देश के युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। कौशल शिक्षा को मूल शिक्षा के साथ जोड़ने की यह नीति भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि प्रौद्योगिकी, नवाचार और रचनात्मक सोच में सुधार लाकर भारत अपने उद्योग और सेवा क्षेत्रों को और सशक्त बना सकेगा। इसके साथ ही कौशल आधारित शिक्षा से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय विकास और स्वदेशी उत्पादों की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, जो अंततः आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। (वर्मा, स. 2020) [15]

भारतीय ज्ञान परम्परा को विश्व स्तर पर पहुँचाने का प्रयास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इस नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और प्राचीन विज्ञान के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुँचाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस नीति का लक्ष्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है ताकि दुनिया भर में भारतीय विचारधारा, कला और संस्कृतियों का सम्मान बढ़े। इसके लिए भारतीय भाषाओं और संस्कृति को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए इस नीति में संस्कृत, प्राचीन भारतीय विज्ञान और योग जैसे विषयों को शिक्षा में शामिल करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया है ताकि भारतीय ज्ञान प्रणाली को वैश्विक स्तर पर पुनः स्थापित किया जा सके। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन करने के लिए आकर्षित करने की रणनीति भी तैयार की गई है। इसके माध्यम से भारत को शिक्षा का वैश्विक हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। (तिवारी, र. 2020) [11] भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए इस नीति में शोध, नवाचार और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत में उच्च शिक्षा और शोध कार्यों को विश्वस्तरीय मानक तक पहुँचाया जाए ताकि भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान वैश्विक रैंकिंग में अपनी उपस्थिति शीर्ष स्थानों पर दर्ज कर सकें। यह नीति

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी की दिशा में भी काम कर रही है। इस नीति के अनुसार, भारत में प्रमुख विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी शाखाएँ खोलने की अनुमति दी जाएगी ताकि भारत में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा का विस्तार हो सके। इसके साथ ही, भारत में विदेशों से छात्रों को आकर्षित करने और उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ बनाई जा रही हैं, जैसे ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल और ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा का विस्तार।

शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार के लिए नए कार्यक्रमों की शुरुवात

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता शिक्षक की भूमिका पर निर्भर करती है। इस नीति में शिक्षक प्रशिक्षण, समझ और व्यवसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के शिक्षक वैश्विक मानकों के अनुरूप हों और वे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सके, इसके लिए इस नीति में शिक्षक प्रशिक्षण के नए तरीके और आधुनिक शिक्षण विधियों को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना की योजना है, जो शिक्षक प्रशिक्षण के सभी पहलुओं पर निगरानी रखेगी और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी। (गुप्ता, म. 2022) [6] इसके अलावा इस नीति में शिक्षकों के लिए नियमित अपडेट और कौशल सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ताकि वे नई शिक्षण विधियों और प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठा सकें और शिक्षक अपने पेशेवर जीवन में निरंतर विकास करते रहें और छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकें। टीचर स्टैंडर्ड्स और नए मानक लागू करने के साथ-साथ, इस नीति में प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कैरियर प्रगति के अवसर देने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि शिक्षक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। इसके तहत, शिक्षकों के लिए अनुकूल कार्य परिस्थितियाँ और प्रोत्साहन योजनाएँ भी शुरू की जाएँगी जिससे उनका मनोबल ऊँचा रहेगा। ब्लेंडेड लर्निंग और ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से, शिक्षकों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम विकासों से अवगत रह सकें। इसके साथ ही शिक्षक शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत, शिक्षक प्रशिक्षण को उच्च गुणवत्ता और समग्र दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया जाएगा ताकि शिक्षक छात्रों की मानसिकता, सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम हो सकें।

राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन से देश के शोध को मजबूती:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत में शोध कार्यों को सशक्त बनाना और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस नीति का मानना है कि शोध देश के वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए एक मजबूत शोध इकोसिस्टम की आवश्यकता है और राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की स्थापना से शोधकर्ताओं को वित्तीय सहायता और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे वे नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इस शोध फाउंडेशन का उद्देश्य यह भी है कि भारत में शोध कार्यों को बेहतर दिशा में मार्गदर्शन दिया जाए, विशेष रूप से कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। इस संस्थान का उद्देश्य देशी और अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और भारतीय शोध के वैश्विक मानक को मजबूत करना है। नई शिक्षा नीति के अनुसार, शोध की गुणवत्ता और समाज में इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शोध कोष उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना भारत के विश्वविद्यालयों और शोध केंद्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध कार्यों के लिए प्रेरित करेगी और साथ ही प्रौद्योगिकी और नवाचार में भारत को अग्रणी बनाएगी। इसके द्वारा स्वदेशी ज्ञान को सशक्त किया जाएगा और भारत के शोध को वैश्विक पहचान मिल सकेगी। (Kumar, A. 2021) [7]

गुरु-शिष्य परंपरा की पुनः स्थापना से विकसित भारत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गुरु-शिष्य परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में गुरु और शिष्य के बीच का संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण था, जिसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा माना जाता था। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य इस परंपरा को पुनः जीवित करना है ताकि शिक्षा केवल साहित्यिक ज्ञान तक सीमित न रहकर एक जीवनदर्शन के रूप में विद्यार्थियों के मानसिक, बौद्धिक और नैतिक दृष्टिकोण को विकसित कर सके। इस नीति में गुरु-शिष्य संबंध को संवेदनशील, रचनात्मक और समाज से जुड़े दृष्टिकोण से पुनः आकार देने का प्रस्ताव है। गुरु-शिष्य परंपरा में शिक्षक का उच्चतम सम्मान और शिष्य की पूर्ण श्रद्धा रही है जो आज के आधुनिक शिक्षा तंत्र में कहीं न कहीं छूट गई है। इस नीति में इस संबंध को पुनः स्थापित करने का लक्ष्य है, ताकि शिक्षक, शिक्षिका न केवल शिक्षक बल्कि मार्गदर्शक, संरक्षक और जीवन के एक साथी के रूप में कार्य करें। (Sharma, N. 2024) [10] इस नीति में शिक्षक के प्रशिक्षण पर जोर देते हुए उन्हें समग्र दृष्टिकोण से विद्यार्थियों की शिक्षा

में शामिल किया गया है, ताकि शिक्षक शिष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में भी सक्रिय रूप से योगदान कर सकें। इस नीति के तहत शिक्षक और छात्र के बीच सामूहिक समझ को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक शिक्षा विधियों के साथ-साथ पारंपरिक गुरुकुल पद्धतियों का समावेश किया गया है। विशेष रूप से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रेरणादायक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थी न केवल ज्ञान प्राप्त करें बल्कि उसे व्यक्तिगत जीवन में लागू करने की क्षमता भी प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति में शिक्षक के चयन, प्रशिक्षण और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से समझ सकें और गुरु-शिष्य संबंध को उचित दिशा दे सकें।

भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण पर बल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत की शिक्षा पद्धति हमेशा से संस्कार, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी रही है और इस नीति का उद्देश्य इस मूल्य आधारित शिक्षा को और सशक्त बनाना है। (Verma, H., & Kumar, A. 2021) [14] इस नीति में भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को शिक्षा के हर पहलू में शामिल करने की बात की गई है ताकि विद्यार्थी न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से समृद्ध हो बल्कि वे अपने संस्कारों और मूल्यों से भी जुड़े रहें। इस शिक्षा नीति के तहत भारतीय भाषाओं को शिक्षा के मुख्य हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है। यह नीति विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर जोर देती है, जिससे वे अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़कर शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके अलावा भारतीय इतिहास, कला, संगीत, साहित्य और संस्कारों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए भी यह नीति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है जिससे आने वाली पीढ़ियाँ अपनी संस्कृतिपूर्ण धरोहर को समझने और संजोने में सक्षम हों। शिक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए इस नीति में संस्कार आधारित शिक्षा की वकालत की गई है जो छात्रों को नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां सिखाती है क्योंकि जब छात्र अपनी संस्कृति और मूल्यों से जुड़े होते हैं तो वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित व वचनबद्ध होते हैं।

शोध पत्र के परिणाम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विकसित भारत के दृष्टिकोण से गहन अधयन्न करने के उपरांत यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस शिक्षा नीति का उद्देश्य एक समावेशी, सशक्त और वैश्विक दृष्टिकोण से भारत को शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बनाना है। इस नीति के प्रभावों का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हुआ

कि शिक्षा में सुधार के माध्यम से न केवल देश की समृद्धि बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाया जा सकता है। इस शोध में यह पाया गया कि मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देने से आधुनिक शिक्षा और सांस्कृतिक पहचान दोनों को एक साथ बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप, शिक्षा का स्तर तो बढ़ेगा ही साथ ही समाज में समानता और समावेशिता की भावना भी मजबूत होगी। इसके अलावा, कौशल आधारित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को महत्व दिए जाने से शिक्षार्थियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए नए अवसर मिलेंगे। शोध और नवाचार के लिए राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन के गठन से भारत में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नई तकनीकी क्रांति और आर्थिक प्रगति में मदद मिलेगी। इस नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण को प्राथमिकता देने से समाज में सशक्तिकरण और एकता को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधारशिला साबित होगी। शिक्षा के हर पहलू में सुधार और समान अवसरों के लिए इस नीति ने जो दिशा निर्धारित की है वह आने वाले वर्षों में भारत को एक सशक्त और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनाने में अपना पूर्ण सहयोग करेगी।

भविष्य के लिए सुझाव

1. शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आधुनिक और प्रासंगिक बनाकर नवीनतम तकनीक और शैक्षिक पद्धतियों को शामिल किया जाए ताकि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें।
2. ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए ऑनलाइन शिक्षा को सुलभ और समावेशी बनाया जाए ताकि हर बच्चा डिजिटल शिक्षा का लाभ उठा सके।
3. स्थानीय उद्योगों और रोजगार की जरूरतों के अनुसार कौशल आधारित शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएं।
4. ग्रामीण अल्पसंख्यक और हाशिए पर बैठे हुए समुदायों को समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान लागू किए जाएं जिससे शिक्षा में समावेशिता सुनिश्चित हो सके।
5. शिक्षा के क्षेत्र में असमानताओं को दूर कर निजी और सरकारी विद्यालयों के बीच गुणवत्ता के अंतर को समाप्त किया जाए और सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान किया जाए।

निष्कर्ष

अंत: में निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के शिक्षा तंत्र में

अभूतपूर्व बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के तहत शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जो न केवल विद्यार्थियों को व्यावसायिक कौशल और आधुनिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करती है बल्कि देश की सांस्कृतिक धरोहर और मातृभाषाओं के संरक्षण के लिए भी कार्य कर रही है। कौशल शिक्षा, शोध और नवाचार और शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह नीति भारत को एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। इस नीति में दिए गए समावेशी और सशक्त शिक्षा के सिद्धांतों से सभी वर्गों और समुदायों को समान अवसर मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार से नई शिक्षा नीति विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक स्थिर आधारशिला प्रदान करती है। हालांकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन और दीर्घकालिक लाभ के लिए सरकारी नीतियों और संसाधनों का सही उपयोग और समाज में जागरूकता की आवश्यकता होगी। अगर इस नीति को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो भारत निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर होकर एक विकसित राष्ट्र बनेगा।

संदर्भ:

AISHE 2021-22 Report (All India Survey on Higher Education), Ministry of Education, Government of India. https://aishe.gov.in/aishe-final-report/

Bal, D., & Singh, K. (2023). National Education Policy-2020: A driving force for higher education of India. International Journal of Research in Library Science, 9(4), 200–209. https://doi.org/10.26761/IJRLS.9.4.2023.1713

Betsurmath, C. G., & Chidambaram, S. B. (2024). National Education Policy 2020, India: A planned change management requisite for higher education institutions. Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8(9), Article 3020. https://doi.org/10.24294/jipd.v8i9.3020

Bose, A., & Vijayvargiya, D. (2024). NEP 2020 and Open Educational Resources: Aligning policies and practices. Gurukul International Multidisciplinary Research Journal, 12(2), 159–165. https://gurukuljournal.com/wp-content/uploads/2024/07/GIMRJ2406IIV12P026.pdf

Chaudhariya, R. (2024). जैन दर्शन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: सिद्धांतों और प्रभावों का विश्लेषण. Naveen Shodh Sansar, 11(3), 1–6. https://nssresearchjournal.com/current-edition-details/NSS8758

गुप्ता, म. (2022), "नई शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति का संरक्षण", भारतीय शिक्षण अनुसंधान पत्रिका, 10(2), 34–48.

Kumar, A. (2021). New education policy (NEP) 2020: A roadmap for India 2.0. In W. B. James, C. Cobanoglu, & M. Cavusoglu (Eds.), Advances in global education and research (Vol. 4, pp. 1–8). USF M3 Publishing. https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=m3publishing

NCERT Annual Report 2021-22 on Education Policy, https://ncert.nic.in/pdf/annualreport/AnnualReport2021-22.pdf

NEP Draft (2020), Ministry of Education, Government of India. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

Sharma, N. (2024). India's National Education Policy (NEP) 2020: Reimagining and revolutionizing
higher education: A review. International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science, 6(7), 3574–3581. https://doi.org/10.56726/IRJMETS60637

तिवारी, र. (2020). "कौशल आधारित शिक्षा की नई दिशा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020", नवभारत प्रकाशन.

Ullah, A. (2024). NEP 2020 and the quest for equity: Promoting inclusion in higher education. MANAVIKI, 16(2), 395–412. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5086672

UNESCO Report (2021), "India's Progress in Education under NEP 2020". https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379171

Verma, H., & Kumar, A. (2021). New Education Policy 2020 of India: A theoretical analysis. International Journal of Business and Management Research, 9(3), 302–306. https://doi.org/10.37391/IJBMR.090308

वर्मा, स. (2020), भारत की शिक्षा प्रणाली का विकास और नई शिक्षा नीति 2020, राजकमल प्रकाशन.